

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर०ए०एस०

राजस्व अपील संख्या 511/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
मोहम्मद हनीफ पुत्र खैर मुबारक जाति मुसलमान निवासी नूरे की भूर्ज, तहसील बाप जिला जोधपुर		1- ताज मोहम्मद पुत्र खैर मुबारक 2- नियाज मोहम्मद पुत्र खैर मुबारक जाति मुसलमान निवासी नूरे की भूर्ज, तहसील बाप जिला जोधपुर 3- उप तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 15-7-2015 जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 80/2013 अनवान ताज मोहम्मद बनाम मोहम्मद हनीफ वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री किसनाराम विश्णोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री पूनाराम अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 2,3 व 15,16 की ओर से।
- 3- शेष रेस्पोंड बावजूद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 17-1-2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि ग्राम नूरे की भूर्ज तहसील बाप के खसरा नंबर 326 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नंबर 328 रकबा 48.06 बीघा कुल 50.04 बीघा भूमि अपीलांट एवं रेस्पोंड संख्या 1 व 2 के पिता खैर मुबारक पुत्र रायधन खां की संयुक्त खातेदारी की थी तथा अपीलांट एवं रेस्पोंड संख्या 1 व 2 के पिता खैर मोहम्मद के फोट होने पर उनके पिता के खातेदारी की भूमि मे उक्त तीनों 1/3 - 1/3 हिस्से पर लगातार शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे थे । परंतु उक्त भूमि का म्युटेशन वर्तमान अपीलांट मोहम्मद हनीफ पुत्र खैर मुबारक अकेले ने पटवारी हल्का एवं उप तहसीलदार से मिलावट कर अपने पक्ष मे कूटरचित अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा होना बताकर उसके आधार पर म्युटेशन संख्या 650 मौजा नूरे की भूर्ज अपने अकेले के हक मे भरवाकर स्वीकृत करवा लिया, जो विधिविरुद्ध होने से उसे निरस्त करवाने बाबत वर्तमान रेस्पोंड संख्या 1 ताज मोहम्मद पुत्र खैर मुबारक ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रथम अपील पेश की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15-7-2015 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 650 मौजा नूरे की भूर्ज को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाप को मृतक खैर मुबारक के 1/3 हिस्से मे उसके विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर संबंधित पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर म्युटेशन की कार्यवाही के निर्देश पारित किये गये । जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे नोटिस की तामिल की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि नोटिस प्रोपर तामिल ही नहीं हए थे तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे आदेशिका दिनांक 24-12-2014 से 21-5-2015 तक दोनो पक्षो के अधिवक्ता गैर हाजिर रहे तो एक्स पार्टी मानते हुए अपील को खारीज कर दी जानी चाहिये थी । उसके पश्चात दिनांक 24-6-2015 को केवल अपीलांट अधिवक्ता ही उपस्थित होने पर रेस्पो0 गैर हाजिर होने पर रेस्पो0 को पुनः नोटिस जारी करना चाहिये था परंतु दिनांक 30-6-2015 को केवल अपीलांट अधिवक्ता को एकतरफा सुनकर पत्रावली आदेश हेतु रखते हुए अपीलाधीन निर्णय मे दोनो ही अधिवक्ता की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया । पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस मे विचाराधीन थी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24-6-2015 मे अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित, मिसल वास्ते पूर्व आदेश की पालना मे तथा बहस हेतु दिनांक 30-6-2015 को तथा दिनांक 30-6-15 को बहस सुनी जाकर आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 15-7-15 को रखी गई तथा उक्त दिनांक को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया इसप्रकार अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा बिना सुने ही पारित किया गया होने से न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार खेर मुबारक के देहांत होने पर अपीलांट के पक्ष मे की गई वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत नूर की भुर्ज के समक्ष प्रस्तुत किया । ग्राम पंचायत नूर की भुर्ज द्वारा वसीयत की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी द्वारा जांच करने के पश्चात वसीयत को सही पाया गया तथा ग्राम पंचायत ने अपीलांट के पक्ष मे एक प्रमाण पत्र जारी कर उप तहसीलदार बाप को प्रेषित किया जिसके आधार पर उप तहसीलदार बाप ने म्युटेशन संख्या 650 स्वीकृत किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उप तहसीलदार बाप द्वारा पारित विस्तृत आदेश दिनांक 14-10-01 का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 15-7-2015 को पारित करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 650 बिना आधार के निरस्त कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत नूरे की भुर्ज द्वारा संबंधित वसीयत की नियमानुसार जांच की गई थी तथा जांच के पश्चात पत्रावली उप तहसीलदार बाप को प्रेषित की गई तथा उप तहसीलदार बाप ने प्रकरण को विवादित होना मानते हुए अपना आदेश धारा 135 (2) लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत विधिसम्मत पारित किया गया इसलिए धारा 135 (2) के तहत पारित निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर फलोदी

का नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15-7-2015 निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 14 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुए म्युटेशन संख्या 650 के विरुद्ध अत्यधिक देरीना अपील पेश की थी तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार किये बिना तथा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित किये बिना ही अपील का निर्णय पारित कर दिया जबकि अपील के निर्णय से पूर्व धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना आवश्यक था इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के पिता खेर मुबारक की स्वअर्जित भूमि थी इस कारण इस भूमि के संबंध में खेर मुबारक को मुंतकील करने का पूर्ण अधिकार था इसलिए उसने उन्ही अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि के संबंध में एक वसीयत मुंतकील की जो नियमानुसार मुस्लिम विधि अनुसार की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि मुस्लिम विधि के अनुसार 1/3 हिस्से से अधिक सम्पत्ति की वसीयत करने पर अन्य वारिसान की सहमति लेना आवश्यक है तथा वसीयत मजमे आम परिवार की सहमति से कर सकता है तथा मेरे मामले में सहमति लेकर वसीयत मेरे पक्ष में की गई है, जो सही है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत लिखित तथा तस्दीकसुदा थी, इस कारण से वसीयत को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने लिखित वसीयत के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 650 को निरस्त करने में कानूनी भूल की है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में वसीयतनामा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना तथा वसीयत अनरजिस्टर्ड होने से वसीयत को नियमानुसार नहीं माना जबकि मुस्लिम विधि में वसीयत रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिका दिनांक 24-12-2014 से 21-5-2015 तक दोनों पक्षों के अधिवक्ता गैर हाजिर रहे तथा दिनांक 24-6-2015 को केवल अपीलांट अधिवक्ता ही उपस्थित रहे तथा दिनांक 30-6-2015 को केवल अपीलांट अधिवक्ता को एकतरफा सुनकर पत्रावली आदेश हेतु रखते हुए अपीलाधीन निर्णय में दोनों ही अधिवक्ता की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय में

रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कोई बहस ही नहीं की थी इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी तथा जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उक्त अपील इस न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी थी इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-7-2015 को निरस्त करने का निवेदन किया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2015 पेज 119, आर.आर.डी.2009 पेज 123 तथा आर.आर.टी.2006 (2) पेज 1092 की निर्णय नजीरे पेश की।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय जो कि विधिसम्मत होने से उसका समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार खैर मुबारक के जायंदा पुत्र हैं परंतु अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 650 अकेले अपीलांट के पक्ष में वसीयत के आधार पर स्वीकृत कर दिया जाने पर उक्त म्युटेशन के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर उक्त नामांतरकरण संख्या 650 को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाप को अपीलाधीन भूमि में से मृतक खैर मुबारक के 1/3 हिस्से की भूमि के संबंध में विधिक प्रक्रिया के द्वारा जांच कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधिक उत्तराधिकार के नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो0गण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में रेस्पो0गण (वर्तमान अपीलांट) के नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये तथा बाद तामिल वर्तमान अपीलांट मोहम्मद हनीफ एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया इसलिए अपीलांट का यह कथन कि सही नहीं है कि नोटिस प्रोपर तामिल नहीं हुए तथा अपीलाधीन निर्णय बिना सुने पारित कर दिया हो।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन वसीयत के आधार पर बिना विवाद के उप तहसीलदार बाप द्वारा स्वीकृत किया गया था इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन निर्विवादित होने से उसकी प्रथम अपील सुनवाई का अधिकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ही होने से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अपीलांट ने जो अतिरिक्त दस्तावेज पेश किये हैं, वे विधिवत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये जाने चाहिये तथा यह भी कथन किया कि यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को मयाद सुमार करते हुए

निर्णय पारित कर दिया है तो द्वितीय अपीलीय न्यायालय को इस बिन्दु पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है इसलिए अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने जवाब उल जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 650 जो कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरकर पेश किया गया जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख ने ग्राम पंचायत की मीटिंग में जांच अपेक्षित होने का नोट अंकित किया तथा उक्त म्युटेशन ग्राम पंचायत के समक्ष जांच हेतु पेश हुआ तथा ग्राम पंचायत नूरे की भुर्ज ने अपंजीकृत वसीयतनामों के संबंध में जांच कर रिपोर्ट दिनांक 13-11-2001 को प्रस्तुत की अर्थात् उक्त तमाम कार्यवाही सम्पन्न होने से अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 650 जो विवादित होने से उसकी अपील निदेशक भू अभिलेख अर्थात् संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष होनी चाहिये थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य था ।

इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता ने अपने जवाब उल जवाब में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय में मयाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना ही अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया, जो दोषपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 650 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया ।

अपीलाधीन भूमि ग्राम नूरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नंबर 326 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नंबर 328 रकबा 48.06 बीघा कुल 50.04 बीघा भूमि अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 1 व 2 के पिता खैर मुबारक पुत्र रायधन खां की खातेदारी की थी । अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार खैर मुबारक के जायंदा पुत्र हैं । खातेदार खैर मुबारक के फौत होने पर उक्त खातेदारी भूमि का म्युटेशन वर्तमान अपीलांट मोहम्मद हनीफ पुत्र खैर मुबारक के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर म्युटेशन संख्या 650 स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन संख्या 650 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष वर्तमान रेस्पों संख्या 1 ताज मोहम्मद पुत्र खैर मुबारक द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15-7-2015 के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 650 को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाप को अपीलाधीन भूमि में से मृतक खैर मुबारक की भूमि के संबंध में विधिक प्रक्रिया के द्वारा जांच कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर

विधिक उत्तराधिकार के नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया । जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है ।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में रेस्पोंगण (वर्तमान अपीलांटगण) के नोटिस प्रोपर तामिल नहीं कराये गये तथा अपीलाधीन निर्णय में रेस्पों की ओर से अधिवक्ता द्वारा कोई बहस नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30-6-2015 में केवल अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनने का ही उल्लेख है, रेस्पों अधिवक्ता की बहस का उल्लेख नहीं होते हुए अपीलाधीन निर्णय में रेस्पों अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय बिना सुनवाई के ही पारित कर दिया । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से उसमें रेस्पों के नोटिस जारी होना पाया जाता है तथा वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया हो । अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन कि उनके द्वारा किसी अधिवक्ता को वकालतनामा ही नहीं दिया तथा अधिवक्ता को निर्देशित नहीं किया जाने के बावजूद उनकी ओर से उपस्थिति दी गई है तो यह तथ्य अपीलांट को अधिवक्ता से ही सत्यापित करना चाहिये तथा अपीलाधीन निर्णय में यदि उपस्थिति दर्ज का उल्लेख है तो अपीलाधीन निर्णय को एक्स पार्टी या बिना सुनवाई के पारित किया हुआ नहीं माना जा सकता है । इसके अलावा अपीलाधीन म्युटेशन वसीयत के आधार पर भरा है तो उसे विवादित नहीं माना जा सकता है तथा अविवादित म्युटेशन की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही था ।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15-7-2015 के विरुद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष लगभग 1 माह विलंब से दिनांक 9-10-2015 को धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार की जाती है ।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन म्युटेशन जो कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में उप तहसीलदार बाप द्वारा वर्ष 2001 में स्वीकार किया गया था, उसे निरस्त करने का कोई कारण या आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं होते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 650 को निरस्त करने बाबत पारित किया गया निर्णय समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है ।

रेस्पोंगण यदि अपीलाधीन भूमि में कोई हक अधिकार होना तथा वसीयत को कूटरचित होना मानते हैं तो सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र है । यह भी उल्लेखनीय है कि म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही में वसीयत एवं गोद जैसे विवादित बिन्दुओं का निर्धारण संभव नहीं है जैसाकि निर्णय नजीर आर.आर. डी. 2009 पेज 123 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष वर्ष 2001 में स्वीकृत किये गये म्युटेशन के विरुद्ध लगभग 12 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है जैसाकि वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1092 तथा आर.आर.डी. 2015 पेज 119 की निर्णय नजीरो में यही अभिनिर्धारित किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15-7-2015 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 650 पर उप तहसीलदार बाप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-10-2001 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17-1-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर